Govt. Registered Social Justice Union

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 04 दिसंबर 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-07, अंक- 66

रायगढ़ में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा नालंदा परिसर : मुख्यमंत्री ने किया भूमिपूजन, रायगढ़ जिले को 137.55 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात

जनादेश दिवस: प्रदेश की महिलाओं को मिली महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त

मोदी की गारंटी के अधिकांश वायदों को एक साल के भीतर ही किया पूरा: विष्णु देव साय

रायगढ़

हमारी 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना की एक हजार रुपए की स्नेह राशि की दसवीं किश्त हमने आपके खाते में आज अंतरित कर दी है। हमारी माताओं-बहनों का आशीर्वाद ही मुझे काम करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारी माताओं-बहनों की आंखों में दिख रही स्वाभिमान की चमक हमारा सबसे बड़ा संतोष है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले में लगभग 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय के आग्रह पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की।

मुख्यमंत्री साय ने अपने उद्बोधन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम दानसरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां की माताओं और बहनों ने सोचा कि अयोध्या धाम में भव्य श्रीरामलला का मंदिर बना है। हम भी गांव के हनुमान मंदिर के बगल में रामलला का मंदिर बनाएं। इन महिलाओं ने महतारी वंदन योजना से मिली राशि से चंदा कर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। माताओं-बहनों के सपने देखने और इनके पूरे होने की कितनी ही कहानियां हैं। मैं अक्सर माताओं-बहनों से इस बारे में पूछता हूँ और हर बार उनकी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कल मैं रायपुर में पीएससी परीक्षा के टापर्स से मिला। उन युवाओं के आंखों में भरोसे की चमक थी। उन्होंने मुझे बताया कि पीएससी परीक्षा में गड़बडिय़ां होने की वजह से उनका भरोसा टूट गया था लेकिन जब हमारी सरकार आई तब हमने पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता के लिए कार्य किया। प्रतियोगी परीक्षा में किये गये भ्रष्टाचार से एक प्रतिभाशाली युवा का भविष्य तो बर्बाद होता ही है सिविल सेवा के ढांचे को भी दीमक लग जाता है। भ्रष्टाचार की जांच के लिए हमने सीबीआई को जिम्मा दिया तो उनका भरोसा फिर लौटा। आज हमने 42 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि से बनने वाले नालंदा परिसर का भी भूमिपूजन किया है, जिससे पीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे युवाओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। हम प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में राजधानी रायपुर के नालंदा की तरह लाइब्रेरी आरंभ कर रहे हैं। यहां हजारों किताबों का संग्रह होगा। वाईफाई की सुविधा होगी। सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को यहां स्टडी मटेरियल मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। हमने भी वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने विजन डाक्यूमेंट बनाया है। विजन डाक्यूमेंट में प्रदेश के तेजी से औद्योगीकरण पर सबसे ज्यादा जोर है। उद्योग धंधों के तेजी से विकास के लिए हमने नई उद्योग नीति बनाई है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में उद्यमियों को नये उद्यम आरंभ करने में बहुत सहूलियत होगी। औद्योगिक वातावरण को बेहतर करने के लिए कनेक्टिविटी सबसे पहली शर्त होती हैं। अगले दो साल में हमारे प्रदेश का रोड नेटवर्क किसी भी विकसित देश की बराबरी का होगा। सरगुजा और बस्तर को एयर कनेक्टिविटी मिल गई है। रेलवे में जिस तरह से अधोसंरचना का कार्य एक दशक में किया गया है उससे भविष्य में यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, मालभाड़े का आवागमन भी बेहद आसान हो जाएगा जो बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी धान खरीदी का समय है। हमारी सरकार ने किसानों की खुशहाली का भी पूरा ध्यान रखा है। हम लोग 3100 रुपए प्रति क्विंटल तथा 21 एकड़ प्रति क्विंटल धान खरीद रहे हैं। पिछली बार हमने 145 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड धान खरीदा था। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य है। हमारी सरकार के एक साल पूरे होने जा रहे हैं। शपथ लेने के अगले दिन ही हमने 18 लाख आवासों को स्वीकृत किया था और तब से मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का सिलसिला अनवरत चलता आया और अब हमने मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वायदों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राहियों को सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने आवास का काम पूरा कर लिया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज के दिन छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में मोदी की सभी गारंटी पूरी हो रही है। गांव और शहरों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में नगरीय विकास के लिए 100 करोड़ रुपए को राशि जारी की गई है। रायगढ़ नगर निगम में ही 60 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में रायगढ़ जिले में किसानों को सिंचाई सुविधा दिलाने के लिए केलो डैम से नहरों का काम पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में रायगढ़ अंचल का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ में हार्टिकल्चर कॉलेज खुलने जा रहा है। यहां नालंदा परिसर का निर्माण सीएसआर मद से निर्मित होगा, जिसका लाभ यहां के छात्रों को यहां मिलेगा।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम पूनम सोलंकी, सत्यानंद राठिया, विजय अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, गुरूपाल भल्ला, श्रीकांत सोमावार, महेश साहू, अरूणधर दीवान, सतीश बेहरा, जगन्नाथ पाणिग्राही, रत्थू जायसवाल, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव सहित गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी लाईब्रेरी

रायगढ़ के मरीन ड्राइव में सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। यह प्रदेश की सबसे बड़ी लाईब्रेरी होगी, यहां वो सारी सुविधाएं होगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है। यहां अध्ययन-अध्यापन का एक ऐसा इको सिस्टम छात्रों को मिलेगा, जिससे वे खुद को प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर सकें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ 5 स्कूली छात्रों ने बटन दबाकर रायगढ़ में बनने जा रहे नालंदा परिसर के वर्चुअल टूर वीडियो का लोकार्पण किया।

नालंदा परिसर में स्मार्ट लाइब्रेरी व स्टडी जोन होगा। हजारों किताबों के संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई-बुक एक्सेस करने की भी सुविधा होगी। स्मार्ट लर्निंग पर फोकस होगा। 24&7 वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा भी छात्रों को यहां मिलेगी। सिविल सर्विसेज के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट की तैयारी के साथ मैथ्स ओलिंपियाड के लिए भी किताबें यहां होगी। कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन होगा। 5 वीं के बाद बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए तैयारी हेतु एक किड्स स्टडी जोन और किड्स लाइब्रेरी भी अलग से तैयार होगा जहां उनके सिलेबस के अनुसार किताबें और स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। कॉन्फ्रेंस हाल के साथ कैफेटेरिया भी होगा।

किसानों ने धान से तौल कर जताया मुख्यमंत्री का आभार

रायगढ़ में विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का किसानों ने धान से तौलकर अभिवादन कर उनका आभार जताया। किसानों ने कहा कि आज किसानों को धान का सर्वाधिक 3100 रुपए मिल रहा है। दो साल के बकाया बोनस की राशि जारी की गई है। उपार्जन केन्द्रों में सुगमता से खरीदी हो रही है। मुख्यमंत्री साय के कृषक हितैषी निर्णयों से किसानों में काफी उत्साह है।

पहली बार माताओ-बहनों ने मुख्यमंत्री के साथ बटन दबाकर महतारी वंदन की दसवीं किश्त जारी की

आज रायगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन की एक सुखद झलक देखने को मिली जब महतारी वंदन योजना की दसवीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रुपए की राशि रायगढ़ जिले की माताओं-बहनों ने मुख्यमंत्री के साथ बटन दबाकर पूरे प्रदेश के हितग्राहियों को लिए जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ 5 स्कूली छात्रों ने बटन दबाकर रायगढ़ में बनने जा रहे नालंदा परिसर के वर्चुअल टूर वीडियो का लोकार्पण भी किया।

रामलला दर्शन से लौटे श्रद्धालुओं ने किया अभिवादन

रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अयोध्या धाम के दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को गुलाब का फूल देकर अभिवादन करते हुए शासन की इस योजना के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही उन्होंने शासन द्वारा तीर्थ यात्रा योजना की पुन: शुरूआत किए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी।

पीएम आवास हितग्राहियों को मुख्यमंत्री साय ने प्रदान किया पूर्णता सर्टिफिकेट

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के 35 हितग्राहियों जिन्होंने अपने आवास निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। उन्हें आवास पूर्णता सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। हितग्राहियों ने शासन के आवास निर्माण की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों के खुद के पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है।

महत्वपूर्ण एवं खास

विक्रांत नहीं ले रहे अभिनय से संन्यास, बोले- लोगों ने गलत समझ लिया

मुंबई (आरएनएस)। अभिनेता विक्रांत मैसी इन दिनों खूब चर्चा में हैं। उनकी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट सिनेमाघरों में लगी है। बीते दिन विक्रांत के एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जिसमें उन्होंने अभिनय को अलविदा करने की बात की।इसके बाद पूरा दिन विक्रांत खबरों में छाए रहे। उनके अभिनय छोडऩे की खबर से प्रशंसक बेहद निराश हो गए।अब खुद विक्रांत ने साफ कर दिया है कि वह एक्टिंग से संन्यास नहीं, बल्कि लंबा ब्रेक ले रहे हैं। विक्रांत ने अपने पोस्ट पर बात की। उन्होंने कहा, मैं अभिनय से संन्यास नहीं ले रहा हूं... बस थक गया हूं। मुझे एक लंबे ब्रेक की जरूरत है। मुझे अपने घर की याद आ रही है। काम के चलते सेहत भी प्रभावित हो रही है। लोगों ने मेरे पोस्ट को सही से पढ़ा नहीं।विक्रांत के इस स्पष्टीकरण के बाद अब बेशक उनके प्रशंसक राहत की सांस लेंगे।

राज कुंद्रा की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी ने जारी किया समन

मुंबई (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अश्लील फिल्मों के कथित अवैध वितरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी राज कुंद्रा को 4 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पहले कुंद्रा को सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने नई तारीख मांगी, जिसके बाद अब उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी की जांच में यह मामला शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही है। जांच का संबंध मई 2022 में दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले से है, जिसमें कुंद्रा और अन्य के खिलाफ मुंबई पुलिस की दो प्राथमिकी और आरोप पत्र आधारित कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने 29 दिसंबर को मुंबई और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर सहित विभिन्न शहरों में कुंद्रा और उनके सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी की थी।

जम्मू-कश्मीर में इस बार दिखेगा ला नीना का असर, भारी बर्फबारी से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

श्रीनगर । आरएनएस

जम्मू-कश्मीर में इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और बर्फबारी से तापमान शून्य के नीचे पहुंच जाएगा। यह भविष्यवाणी भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने की।

रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आईएमडी के निदेशक डॉ मुख्तर अहमद ने बताया कि सर्दी बढऩे के साथ ला नीना का प्रभाव तेज हो जाएगा।उन्होंने बताया कि ला नीना से पहले भी कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है और इस साल, यह काफी तीव्र हो रहा है, जिससे लगातार बर्फबारी की उम्मीद है।

कश्मीर घाटी में अच्छी सर्दी पडऩे के संकेत पहले ही मिल चुके हैं। नवंबर में यहां पारंपरिक सर्दी की शुरूआत होती है और इस बार पिछले महीने पहाड़ी क्षेत्रों में 3 बार हल्की बर्फबारी हो चुकी है।समय से पहले बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दिख रही है और रात का तापमान लगातार शून्य डिग्री सेल्सियस और माइनस 5 डिग्री सेल्सियस के बीच है।जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में सामान्य से अधिक वर्षा होने से अधिक ठंड की संभावना है।

पिछले साल अल नीनो के कारण क्षेत्र में वर्षा कम हुई थी और तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई थी, जिससे मौसम विशेषज्ञ काफी चिंतित थे। पिछले कुछ वर्षों से जम्मू-कश्मीर अत्यधिक मौसम परिवर्तनों से जूझा है।इस बार ला नीना के वापस आने से अच्छी बर्फबारी के साथ कड़ाके की सर्दी का अनुमान है, जिससे पर्यटकों की आमद बढ़ सकती है।बर्फबारी से स्थानीय लोगों की चुनौतियां भी बढ़ेगी और परिवहन सेवाएं भी प्रभावित होंगी।

अल नीनो एक तरह की मौसमी घटना है, जिसकी वजह से मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का पानी सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाता है और पूर्व से पश्चिम बहने वाली हवाएं कमजोर पड़ती हैं।ला नीना का असर अल नीनो से ठीक उलटा है। इसमें पूर्व से बहने वाली हवा तेज गति से चलती हैं, जिससे समुद्री सतह का तापमान कम हो जाता है।इससे उत्तर-पश्चिम में मौसम ठंडा होता है।

तमिलनाडु में आई बाढ़ को लेकर पीएम मोदी ने सीएम एमके स्टालिन से की फोन पर बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु में बाढ़ के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से फोन पर बात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तमिलनाडु के जिले विल्लपुरम में आई बाढ़ की वजह से चेन्नई-तिरुचिरापल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात प्रभावित है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा से 69 लाख परिवार और 1.5 लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से 2,000 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है। वहीं मौसम विभाग ने इस संबंध में बताया कि उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी के ऊपर चक्रवाती तूफान फेंगल कमजोर होकर कम दबाव वाले क्षेत्रों में तब्दील हो गया। इससे विल्लुपुरम और आसपास के क्षेत्र बाढ़ से पानी-पानी हो गए। तमिलनाडु का विल्लुपुरम जिला मौजूदा समय में बाढ़ के कहर से त्राहि-त्राहि कर रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था और पीड़ितों को हरसंभव मदद का भी भरोसा दिलाया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावितों से बात करके उनके बीच राहत सामग्री भी वितरित की। इस बाढ़ की वजह से रेलवे ने अपनी तरफ सेवाओं को प्रभावित कर दिया है।

परिवहन निगम की बस और कार में आमने-सामने टक्कर, 5 मेडिकल छात्रों की मौत

अलप्पुझा । आरएनएस

केरल के अलप्पुझा जिले में सोमवार रात को भारी बारिश के बीच भीषण सडक़ दुर्घटना हुई, जिसमें 5 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई।हादसा कलारकोड इलाके में रात करीब 10 बजे हुआ है। मृतकों की पहचान आयुष शाजी, श्रीदीप वलसन, मुहम्मद जब्बार, देवनंदन और मुहम्मद इब्राहिम के रूप में हुई है।सभी मृतक अलप्पुझा के थिरुमाला देवास्वोम मेडिकल कॉलेज में रूक्चक्चस् की पढ़ाई कर रहे थे और प्रथम वर्ष के छात्र थे।

पुलिस ने बताया कि मेडिकल छात्रों की कार में 7 लोग सवार थे और वे अलपुझा जा रहे थे, जबकि केरल राज्य सडक़ परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बस कायमकुलम जा रही थी।सोमवार रात को भारी बारिश के कारण सडक़ पर दिखना मुश्किल था, जिससे तेज रफ्तार कार और बस आमने-सामने टकरा गए।हादसे में जान गंवाने वाले 2 छात्र लक्षद्वीप के, जबकि अन्य केरल के हैं। कार सवार 2 अन्य छात्र समेत बस यात्री भी घायल हुए हैं।

पुलिस ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार को काटकर छात्रों के शवों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल 2 छात्र अस्पताल में भर्ती हैं।हादसे का कारण लगातार हो रही तेज बारिश और कम दृश्यता थी। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लग गया।वहीं केरल में कन्नूर के कल्लेरीराममाला में 2 केएसआरटीसी बस भारी बारिश के कारण आमने-सामने टकरा गईं, जिससे 34 यात्री घायल हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर 27 नवंबर को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, फिर बस से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 5 डॉक्टरों की मौत हो गई थी। सभी सैफई मेडिकल कॉलेज के छात्र थे।

केंद्र ने राज्यों को विशेष सहायता के रूप में 50,571 करोड़ रुपये किए जारी

नई दिल्ली । आरएनएस

केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं में खर्च बढ़ाने के लिए अपनी 'पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता' योजना के तहत राज्यों को 50,571.42 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, पंजाब और तेलंगाना को छोडक़र 28 राज्यों में से 23 ने चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई ब्याज मुक्त

सुविधा का लाभ उठाया।

केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस सुविधा के साथ सबसे अधिक राशि 7,007.93 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को जारी किए गए।

इसके बाद मध्य प्रदेश को 5,074.94 करोड़ रुपये, बिहार को 5,408.88 करोड़ रुपये, राजस्थान को 4,552.01 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 4,416.23 करोड़ रुपये, असम को 3,181.97 करोड़ रुपये, ओडिशा को 3,085.44 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 2,617.70 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 2,616.27 करोड़ रुपये और कर्नाटक 2,272.87 करोड़ रुपये दिए गए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में राज्यों के लिए केंद्र की पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया है।

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को केंद्र की विशेष सहायता योजना के तहत पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

इस योजना के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सडक़, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इस योजना के तहत जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना में राज्यों के हिस्से को पूरा करने के लिए भी धन मुहैया कराया गया है, ताकि इन क्षेत्रों में परियोजनाओं की गति बढ़ाई जा सके।

इस योजना के कुछ हिस्से या तो सुधारों से जुड़े हैं या फिर क्षेत्र विशेष परियोजनाओं के लिए हैं।

इस योजना के तहत राज्यों को राज्य सरकार के वाहनों और एंबुलेंस को स्क्रैप करने, पुराने वाहनों पर देनदारियों को माफ करने, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए व्यक्तियों को कर रियायतें देने और स्वचालित वाहन परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

इसके अलावा, राज्यों को शहरी नियोजन और शहरी वित्त में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवास स्टॉक बढ़ाना है।

इस योजना का एक अन्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा को आगे बढ़ाना और प्रत्येक राज्य में यूनिटी मॉल के निर्माण के माध्यम से 'एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी)' की अवधारणा को बढ़ावा देना है।